

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 20 जनवरी, 2010
विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये उत्तराखण्ड राज्य सहकारी
परिषद के गठन एवं संचालन (राज्य सेक्टर) हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-7409/नियोज/सहकारी परिषद/2009-10 दिनांक 07 जनवरी, 2010 एवं पत्र संख्या-1053/XIV-1/2009 दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कि उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद के गठन एवं संचालन में उल्लिखित मदों हेतु रु० 10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) की धनराशि निम्नांकित शर्तों के अधीन अनुमोदित किये जाने की श्री राज्यपाल सख्त स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) संस्था द्वारा केवल आवश्यक व्यय ही किया जायेगा।
- (2) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय।
- (3) इस सम्बन्ध में सचिव राज्य सहकारी परिषद द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में परिषद के संचालन एवं गठन पर वित्तीय सहमता की धनराशि नियमानुसार स्वीकृति के पश्चात् ही व्यय की जाय।
- (4) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि का व्यय परिषद को अनुमोदित सुविधाओं/मदों पर वार्षिक व्यय तथा संगत नियमों के अन्तर्गत विलों के सत्यापन के उपरान्त ही की जाय।
- (5) उक्त धनराशि का उपयोग अन्यत्र अथवा किसी ऐसी मद में किया जायगा है, जो अनुमोदित नहीं है, तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- (6) अनुमोदित धनराशि के साप्तेक व्यय का व्यय विवरण अगले माह की 5 तारीख तक बी०एम०-13 प्रपत्र पर नियमित रूप से वित्त विभाग/शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (7) उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/रक्षक अधिकारी की पूर्व स्वीकृति

(2)

अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय कतों समय मितव्ययिता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता-आयोजनागत-00-800-अन्य व्यय-20-सहकारी परिषद का गठन एवं संचालन 00-20-सहायक अनुदान/असादान /राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अधिसूचना-334/XXVII-4/2009 दिनांक 14.01.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या- 38 /XIV-1/10-5(8)/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. मन्त्र उपसचिव, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी अल्मोड़ा/देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य/संरिष्ठ कोषाधिकारी अल्मोड़ा/देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एनआईओसीओ, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, उत्तराखण्ड सहकारी परिषद।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनु सचिव।